# न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 12 / 2017 (76 एल .आर. एक्ट)

उनवान

विजेन्द्र सिंह उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री नारायन सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम चपरौली तहसील व जिला धौलपुर।

........................अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, मनिया जिला धौलपुर।

.................................रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 11.01.2017 प्र.संख्या 63 / 2016 उनवानी विजेन्द्र सिंह बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री भीष्मप्रताप सिंह उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक– 13.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 11.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार मनियॉ ने आराजी खसरा नंबर 512 किस्म गैर मुमकिन रास्ता रकवा 03 विस्वा भूमि वाके ग्राम चपरौली तहसील धौलपुर पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, पैनल्टी राशि आरोपित करने एवं 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी / अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष की गई। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा उक्त अपील, अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2017 से खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है एवं ना ही उनके द्वारा कोई अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मनियॉ द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिर्पोट के आधार पर अपीलाण्ट को बिना सुने सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर के समक्ष विवादित आराजी पर भविष्य में कभी भी कब्जा नहीं करेगा, इस आशय का शपथ–पत्र भी पेश कर दिया, किन्तु फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा माफ न करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नही आता है। अपने विशेष कथन में अपीलाण्ट द्वारा भविष्य में कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नही करेगा, इस आशय का शपथ पत्र वक्त बहस देने का कथन करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर सिविल जेल की सजा माफ करने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है। जिस पर अपीलांट द्वारा अवैधानिक कब्जा किया गया है। अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नही है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी नही है। अपीलाण्ट ने विवादित भूमि पर पूर्व में भी संवत 2072 रबी में अतिक्रमण किया था इस बात की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित होती है। अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में ही आता है एवं ऐसे पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के खिलाफ सिविल जेल एंव शास्ति कायम करना उचित ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जॉच उपरान्त ही निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई कानूनी भूल नही की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट का प्रमुखता से यह कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मनियॉ द्वारा सुनवाई का अवसर नही दिया व उन पर कोई नोटिस तामील नही हुआ है एवं विशेष कथन में कब्जा छोडे जाने का शपथ– पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाबजूद तहत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा सिविल जेल की सजा माफ नही की। हमने दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्राबलियों का अवलोकन किया। नायब तहसीलदार मनियॉ की पत्रावली में तामीलशुदा नोटिस संलग्न हैं, जो अप्रार्थी/अपीलाण्ट विजेन्द्र सिंह स्वयं द्वारा प्राप्त किया गया है। अतः अपीलाण्ट का यह कथन कि सुनवाई का अवसर नहीं मिला उचित नहीं है। अपीलाण्ट ने अपने विशेष कथन में निवेदन किया है कि उनके द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर के समक्ष प्रथम अपील में अतिक्रमण हटाये जाने का शपथ–पत्र, प्रस्तुत कर दिया है। कथित रूप से अतिक्रमण हटा लेने मात्र से, अपीलाण्ट अप्रार्थी दण्ड के दायित्व को नही टाल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मनियॉ ने उचित रूप से पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर 15 दिवस की सिविल जेल आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही पाते हैं।

6. वक्त बहस अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपीलाण्ट की ओर से पुनः अतिक्रमण नही करने का परिवचन (UNDERTAKING) देने की तत्परता दर्शाई गई है। चूंकि भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 अन्तर्गत सिविल जेल सजा का उद्‌देश्य, अतिक्रमी को निरूद्ध कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना ही है, जिसकी पूर्ति अपीलाण्ट की अन्डरटेकिंग से होती है। अतः हम, अपील अल्पांश स्वीकार करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मनियॉ को निर्देशित करना चाहेंगें कि सिविल जेल क्रियान्वयन के क्रम में गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने से पूर्व मौके पर सत्यापन कर लेवें, यदि अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटाना पाया जावें एवं अपीलाण्ट भविष्य में अतिक्रमण नही करने का परिवचन दिनांक 18.07.2018 तक प्रस्तुत कर देवें, तो 15 दिवस की सिविल जेल सजा स्थगित रखें। अपीलाण्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर सिविल जेल की सजा के क्रियान्वयन के साथ–साथ भू राजस्व अधिनियम की धारा 91(6) अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही करें।

7. अतः अपील अपीलांट अल्पांश स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाये जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official